

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -761/2014/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जे.के. डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक।

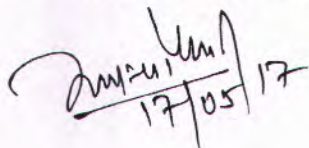
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17.05.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 82/आरवैट/2003 में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.10.2013 के विरुद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 23, 24 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि 2010-11 का त्रैमासिक विवरण प्रपत्र वेट 10 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट 10A समयावधि पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से सन्तोषप्रद प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम धारा 58 के अन्तर्गत 21,100/- रुपये की शास्ति आरोपित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.2013 पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने राजस्थान विक्रय अधिनियम 2006 के नियम 48 की पालना नहीं करने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.2013 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.10.2013 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को इस लिए अपास्त कर दिया कि कर निर्धारण

लगातार.....2.


17/05/17

अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2013 पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित करने से पूर्व नोटिस साध्य डाक द्वारा पारी किया गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात् उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः स्पिड पोस्ट से प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। जिससे यह मानकर शास्ति पारित करना की व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरणों के तथ्यों से परे है। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने कथन किया कि बिना नोटिस तामील कराये आदेश पारित करना नियम 48 के विरुद्ध है। विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् पाया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस तामील के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.2013 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिसूचना क्रमांक 3011 [F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 20.01.2013 के अनुसार आलौच्य अवधि 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 थी। जबकि व्यवहारी द्वारा उक्त विवरण प्रपत्र 10A दिनांक 28.12.2012 को 211 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 की अवधि के विवरण पत्र वेट-10A, 211 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण उसके विरुद्ध कर निर्धारण आदेश 04.02.2013 द्वारा 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 21,100/- रुपये विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.10.2013 द्वारा उक्त 21,000/- रुपये की शास्ति को अपास्त कर दिया गया।
6. विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 21 तथा नियम 19 एवं नियम 19ए में निम्न प्रकार उपबंधित है:-

Sec. 21 FILLING OF RETURN -

- (i) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner,

लगातार.....3.

Amrinder
17/05/17

and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

- (ii) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.
 - (iii) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may be a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.
7. नियम 19(1) से 19(10) तक विवरण प्रपत्र किन को किस प्रकार से पेश करने की स्थिति स्पष्ट की गयी है, जिसमें व्यवसाइयों के लिए त्रैमासिक व वार्षिक विवरण पत्र एवं किन व्यवसाइयों को केवल वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करना है, का उल्लेख किया गया है तथा विवरण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसमें से नियम 19(1) एवं 19(10) का यहा पर उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार है:-

Rule 19 (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10, VAT-10A and VAT-11, as the case may be.

Rule 19(10) :- Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.

8. इस अधिनियम की धारा 58 **Penalty for failure to furnish return** से संबंधित थी जिसे Rajasthan Finance Act, 2011 द्वारा दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT_Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए अधिसूचना क्रमांक 3011[F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 20.01.2013 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 थी। अतः अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात् की अवधि के लिए विवरण प्रपत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।

[Signature]
17/05/17

लगातार.....4.

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की यह अपात्ति रही है कि विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आलौच्य अवधि 2010-11 के लिये वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी जबकि नियम 19A प्रभावी था। लेकिन वर्तमान प्रकरण में विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जा सकता था, न कि शास्ति। विलम्ब शुल्क का दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी स्वयं व्यावसायिक पर ही है। वार्षिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर नियम 19ए के अनुसार व्यवहारी को कर निर्धारण से पूर्व विलम्ब शुल्क के आरोपण के लिये नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की आपत्ति सारहीन है।
10. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह निर्विवादित है कि वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट 10A, 211 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 58 के अधीन व्यवहारी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरण प्रपत्र 10A प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये आरोपित शास्ति 21,100/- रुपये आरोपित की गयी। जबकि धारा 58 दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT_Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि "इसके पैरा संख्या 8 में जो तालिका दर्शायी गयी है उसमें वेट-10ए की रिटर्न दिनांक 28.12.2012 को 211 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर धारा 19ए के अधीन 21,100/- रुपये विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया।" कर निर्धारण आदेश के पैरा संख्या 16 में कुल दायित्व में 21,100/- रुपये की राशि को शास्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा पैरा संख्या 8 में भी तालिका के ऊपर धारा 58 के अधीन शास्ति आरोपित किये जाने का उल्लेख है। किन्तु यहां उल्लेखनीय है कि धारा 58 दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। आलौच्य अवधि 2010-11 के लिये वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी जबकि नियम 19A प्रभावी था। लेकिन वर्तमान प्रकरण में विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जा सकता था, न कि शास्ति।
11. आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। जिसके लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को नियम 19A की पालना में विलम्ब शुल्क का भुगतान करना था। यह विलम्ब शुल्क विहित समयावधि के पश्चात् विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने या कर निर्धारण तक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने का

लगातार.....5.

Amr...
17/05/17

पारिणामिक (Consequential) प्रभाव का परिणाम है। विलम्ब शुल्क स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। अतः व्यवहारी के विरुद्ध नियम 19A के तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाना न्यायसंगत है। आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क के लिये नियम 19A के संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

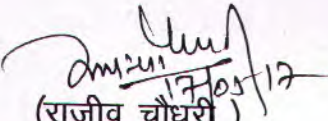
01-04-2012 to 31-03-2013 (sub. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment Rule) Rules 2012 (S.No. 2905 dated 30-03-2012)W.e.f. 01-04-2012

"19A Late Fee :- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

इस प्रकार जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि यदि व्यवहारी मासिक करदाता है, तब नियम 19A के उक्त प्रावधान के अनुसार व्यवहारी के विरुद्ध 100/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम 25,000/- रुपये तक विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता तथा मासिक कर दाता के अन्यथा होने पर 50 रुपये जो अधिकतम 5000/- रुपये तक विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। जबकि कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2013 में धारा 58 के तहत व्यवहारी के विरुद्ध विवरण प्रपत्र 10A को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये आरोपित शास्ति 21,100/- रुपये आरोपित किये गये। जबकि कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2013 को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी। नियम 19ए प्रभावी था। नियम 19ए के अनुसार विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क आरोपित किये जाने का प्रावधान है न कि शास्ति। अतः कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2013 एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.10.2013 को पारित करने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने से उक्त दोनों आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विवरण प्रपत्र 10ए विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये नियम 19ए के तहत कार्यवाही करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को वर्तमान प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना विधि सम्मत है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.10.2013 तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.2013 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवरण प्रपत्र 10ए विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये नियम 19ए के तहत कार्यवाही कर पुनः विधिनुसार आदेश पारित करें।

13. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य